[2009] 5 एस.सी.आर. 72

रानी गुप्ता एवं अन्य।

बनाम

मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य

(2009 की सिविल अपील संख्या 2241)

अप्रैल 8, 2009

[एस.बी. सिन्हा और साइरियक जोसेफ, न्यायाधिपतिगण]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

मृतक की आय- भविष्य की आय की गणना- उचित गुणक को अपनाया जाना चाहिए: निर्भरता के नुकसान का आकलन करने के लिए, मृत्यु के समय वास्तविक सकल आय को अधिकतम में जोड़कर एक औसत सकल भविष्य की मासिक आय प्राप्त की जानी चाहिए। जो मृतक को मिल सकता था अगर उसकी अकाल मृत्यु न हुई होती- ट्रिब्यूनल ने मृतक की उम्र 46 वर्ष मानी और इस तथ्य को कि उसने बैंक का ऋण चुका दिया था, सही माना कि उस समय मृतक की आय दोगुनी हो गई होगी उच्च न्यायालय द्वारा जो10 का गुणांक किया है जो कानून की दृष्टि

से बुरा नहीं है। धाराएं146 और 147-अपने दोस्त की कार में यात्रा कर रहे व्यक्ति की कार दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई- कार का बीमा "निजी कार पैकेज पॉलिसी" के तहत किया गया- अभिनिर्धारित किया गया- बीमाकर्ता उत्तरदायी होगा- क़ानून की व्याख्या।

बीमा

"निजी कार पैकेज पॉलिसी"- धारा 11-खंड (1)(i) तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व- कार में यात्रा करने वाला व्यक्ति- किराए पर या मुफ्त में नहीं ले जाया गया- बीमाकर्ता का दायित्व- समझाया गया।

क़ानूनों की व्याख्या: मोटर वाहन अधिनियम -अभिनिर्धारित: एक लाभकारी कानून है- इसके प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए लेकिन यह अन्यायपूर्ण संवर्धन पर विचार नहीं करता है।

अपीलकर्ता का पति, एक व्यवसायी, अपने मित्र की कार में यात्रा करते समय, जिसका बीमा 'निजी कार पैकेज पॉलिसी'के तहत किया गया था, कार दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई। ट्रिब्यूनल ने मृतक की वार्षिक आय 1,89,500 रुपये आंकी, और यह ध्यान में रखते हुए कि मृतक की उम्र 46 वर्ष थी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों ने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली थी, 13 का गुणक लागू किया। ट्रिब्यूनल ने कटौती की व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3, कुल 17,40,000/- रुपये का मुआवजा दिया गया। बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील पर, उच्च न्यायालय ने

10 का गुणक लागू किया, निर्भरता की हानि का आंकलन 1,87,500 प्रति वर्ष रुपये पर किया। श्रम इनपुट के रूप में 2/3 विभाजित, यानी व्यवसाय में मृतक का व्यक्तिगत इनपुट और पूंजीगत संपत्ति से उपज के रूप में 1/3 माना जाता है और मृत्यु के कारण होने वाली हानि 12,50,000/- रुपये होती है। इसमें आगे कहा गया कि 6,25,000/- रुपये की शेष हानि की भरपाई परिवार द्वारा पूंजीगत संपत्ति से की जा सकती है।

मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा दायर अपील में, यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने 13 के बजाय 10 का गुणक लागू करके गलती की। यह प्रस्तुत किया गया कि वार्षिक निर्भरता के उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालय को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि मृतक का ऋण 14,00,000/- रूपये चुकाया गया था। जिससे उन्होंने एक औद्योगिक भूखण्ड खरीदा था।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया।

1.1. किसी व्यक्ति, जो परिवार का कमाऊ सदस्य था, की मृत्यु से उत्पन्न मुआवजे की राशि का निर्धारण बड़ी संख्या में कारकों पर निर्भर करेगा; उनमें से एक उसकी नौकरी या व्यवसाय की प्रकृति थी जो वह कर रहा था। उक्त उद्देश्य के लिए, उसकी मृत्यु के समय की वास्तविक सकल आय को उस अधिकतम राशि में जोड़कर एक औसत सकल भविष्य की

मासिक आय निकाली जानी चाहिए, जो उसे मिल सकती थी, यदि उसकी समय से पहले मृत्यु नहीं हुई होती। [पैरा 12] [729-एफ]

1.2. अधिकरण ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि थोड़े ही समय में, मृतक बैंक से लिया गया पूरा ऋण चुकाने में सक्षम हो गया और इस प्रकार, एक औद्योगिक भूखंड का मालिक बन गया और इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रासंगिक समय पर उनकी आयु केवल 46 वर्ष थी, उन्होंने सोचा कि उनकी मृत्यु का समय उनकी आय दोगुनी हो गई होगी। अधिकरण का दृष्टिकोण सही था. [पैरा 12] [729-जी, एच; 730-ए] सरला दिक्षित बनाम बलवंत यादव (1996) 3 एससीसी 179, पर निर्भर किया गया।

1.3. भारत में औसत जीवन प्रत्याशा भी उन कारकों में से एक है जिसे औसत सकल भविष्य की मासिक आय की गणना के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत में अब औसत जीवन प्रत्याशा 60-61 वर्ष है। व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों और अन्य वैधानिक देनदारियों जैसे कि आयकर का भुगतान आदि को घटाना आवश्यक है। आमतौर पर, और केवल अपवादों के अधीन, मृतक की आय के 1/3 के बराबर एकमुश्त राशि, यानी, जीवन यापन और विविध व्यय आय से कटौती की जानी चाहिए। स्थायी विकलांगता के मामले में, जहां घायल को बहुत छोटी सी चीज़ के लिए भी दूसरे की सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, उक्त राशि में

कटौती करने के निर्देश पर जोर नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार, 1/3 की कटौती सामान्य नियम है। प्रासंगिक सिद्धांत को लागू करने पर, गुणक वार्षिक निर्भरता को जीवन प्रत्याशा से गुणा करके मृतक की आयु को घटाकर प्राप्त किया जाएगा। [पैरा 14 और 15] [730-एफ; 731-एच; 732-ए; 732-ए-सी]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव (2008) 2 एससीसी 763 और सुनील कुमार बनाम राम सिंह गौड़ और अन्य। (2007) 12 स्केल 792, जी पर निर्भर किया गया।

1.4. दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट गुणक को मार्गदर्शक के रूप में लिया जाना चाहिए, लेकिन मृत्यु के मामलों में मुआवजे की गणना के लिए यह निर्णायक नहीं हो सकता है। वास्तव में, गुणक शब्द का उपयोग केवल स्थायी विकलांगता के मामले में क्षति की गणना के उद्देश्य से किया गया है, न कि मृत्यु के मामले में, जैसा कि संलग्न नोट 5 और 6 से पता चलता है। हालाँकि, किसी दिए गए मामले में दूसरी अनुसूची के संदर्भ में भी जहां मुआवजा बिना गलती दायित्व के आधार पर देय है, गलती दायित्व के मामले में मुआवजे की राशि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट राशि से अधिक हो सकती है। [पैरा 19 और 22] [735-एच; 736-ए; 736-एफ]

हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र एस.आर.टी.सी. (1999) 1 एससीसी 90 और डेविस बनाम पॉवेल डफ्रिन एसोसिएटेड कोलियरीज लिमिटेड (1942 (1) ईलाहाबाद ईएलआर 657, संदर्भित)

हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियम खंड 34, का उल्लेख किया गया है।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन (2002) 6 एससीसी 281; महाप्रबंधक, केरल एस.आर.टी.सी. बनाम सुसम्मा थॉमस (1994) 2 एससीसी 176 और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चार्ली (2005) 10 एससीसी 720, पर भरोसा किया।

1.5. मौजूदा मामले में, मृतक एक व्यवसायी था। परिवार की निर्भरता का वास्तविक नुकसान व्यवसाय चलाने में उनके योगदान से हुआ। व्यवसाय की संपत्तियाँ बनी रहीं। इसलिए, उस कारक को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि निर्धारित की जानी आवश्यक थी। इसलिए, 10 के गुणक के प्रयोग को कानून की दृष्टि से बुरा नहीं कहा जा सकता, जिसके अनुसार मुआवजे की राशि 12,50,000/- रुपये होगी। हालाँकि, उच्च न्यायालय की यह राय पूरी तरह से सही नहीं हो सकती है कि शेष नुकसान की भरपाई की जा सकती है, लेकिन इस न्यायालय को उक्त प्रश्न पर और अधिक गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय सही है। [पैरा 24 और 25] [736-एच; 737-ए; 737-ए-बी]

2. (मोटर वाहन अधिनियम) एक लाभकारी विधान है, उसके प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए लेकिन यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि यह अन्यायपूर्ण संवर्धन पर विचार नहीं करता है। [पैरा 17] [734-ई]

केस कानून संदर्भ:

(1996) 4 एससीसी 362 पैरा 9

(2007) 2 स्केल 227 पैरा 9

(1996) 3 एससीसी 179 पैरा 13

(2008) 2 एससीसी 763 पैरा 14

(2007) 12 स्केल 792 पैरा 15

(1942 (1) ईलाहाबाद ईएलआर 657 पैरा 17

(1999) 1 एससीसी 90 पैरा 17

(2005) 10 एससीसी 720 पैरा 17

(2002) 6 एससीसी 281 पैरा 17

(1994) 2 एससीसी 176 पैरा 17

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2009/2241।

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के 2006 की एमएसी अपील संख्या 986 में निर्णय और आदेश दिनांक 31.5.2007 के विरूद्ध।

अपीलकर्ताओं की ओर से अशोक के. महाजन और शांता देवी रमन।

प्रत्यर्थीगणों की ओर के. ए. डे, राजेश दिवेदी, पबित्रा दिसवाल और देबासिस मिश्रा।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस.बी. सिन्हा, न्यायाधिपति

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2006 के एमएसी नंबर 986 में पारित दिनांक 31.5.2007 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत पहले प्रत्यर्थी द्वारा अपील की गई थी। (संक्षेप में, 'अधिनियम') की अनुमति दी गई थी।

3. अपीलकर्ता ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर कर अपने पति प्रवीण कुमार गुप्ता की मौत के लिए मुआवजे के भुगतान की प्रार्थना की, जो अपने दोस्त श्री अवतार सिंह द्वारा संचालित एक निजी इंडिका कार में यात्रा कर रहे थे। श्री अंकित और श्री राजेंद्र जिंदल (मृतक) कुछ व्यवसाय प्रचार कार्य में भाग लेने के बाद आगरा से लौट रहे थे। उक्त कार के पेड़ से टकराने के कारण यह हादसा हुआ। प्रवीण कुमार गुप्ता और राजेंद्र जिंदल की मौके पर ही मौत हो गई। अंकित को चोटें आईं।

4. विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष, उठाए गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या कार में एक यात्री जिसे लापरवाही से चलाया जा रहा था, बीमा की पॉलिसी द्वारा कवर किया जाएगा।

5. विद्वान न्यायाधिकरण ने रेस इप्सा लोकिटर के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि श्री अवतार सिंह तेजी और लापरवाही से कार चला रहे थे। मृतक द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न को ध्यान में रखते हुए, विद्वान न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसकी वार्षिक आय 1,87,500/- रुपये थी। मृतक की उम्र और बच्चों के वयस्क होने को ध्यान में रखते हुए, मुआवजे की राशि निर्धारित करने में 13 के गुणक को लागू किया गया था। उसकी वार्षिक आय में से व्यक्तिगत उपयोग के लिए वार्षिक आय का 1/3 हिस्सा घटाने पर, मुआवजे की कुल राशि निम्नलिखित शर्तों के अनुसार निकाली गई:

वार्षिक आय रु. 1,25,000

भविष्य में आय में वृद्धि रु. 2,50,000

रु. 3,75,000

मध्य/औसत आय रु. 1,87,500

कम: व्यक्तिगत उपयोग के लिए 1/3

एक खपत रु. 62,500

वार्षिक निर्भरता रु. 1,25,000

इस तरह

क) वित्तीय निर्भरता का नुकसान रु. 16,25,000

(1,25,000 x 13)

बी) कंसोर्टियम का नुकसान रु. 25,000

ग) प्यार और स्नेह की हानि रु. 75,000

(25,000 X 3)

घ) अंत्येष्टि व्यय रु. 15,000

सम्पूर्ण प्रतिकर 17,40,000 रुपये"

6. पहले प्रत्यर्थी ने उसके विरुद्ध अपील दायर की।

7. उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या मृतक एक निजी कार में एक निःशुल्क यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था, जो 'तीसरे पक्ष' के अर्थ में आएगा और इस प्रकार, धारा 147 के तहत वैधानिक नीति के अंतर्गत कवर किया जाएगा। अधिनियम का.

विद्वान न्यायाधीश ने देखा कि पॉलिसी "निजी कार पैकेज पॉलिसी" थी जैसा कि 1.7.2002 से टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसके नियम और शर्तें हैं:

"धारा II- तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व

1. यहां अनुसूची में निर्धारित दायित्व की सीमाओं के अधीन, कंपनी वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न दुर्घटना की स्थिति में बीमाधारक को उन सभी राशियों की क्षतिपूर्ति करेगी, जिनका भुगतान करने के लिए बीमाधारक निम्न के संबंध में कानूनी रूप से उत्तरदायी होगा।

(i) वाहन में सवार लोगों सहित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट (बशर्ते ऐसे सवारों को किराए या इनाम के लिए नहीं ले जाया गया हो) लेकिन जब तक मोटर वाहन अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक हो, कंपनी ऐसा नहीं करेगी। बीमाधारक द्वारा ऐसे व्यक्ति के रोजगार के दौरान और उसके दौरान ऐसी मृत्यु या चोट उत्पन्न होने पर उत्तरदायी होगा।

(ii) बीमाधारक की संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति को नुकसान, जो बीमाधारक के ट्रस्ट या हिरासत या नियंत्रण में है।"

8. इसके अलावा यह राय दी गई कि धारा 146 और 147 का उद्देश्य यह है कि बीमा की पॉलिसी को माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि सहित किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में

दायित्व को कवर करना चाहिए, जिसे माल में ले जाया जा सकता है। वाहन/गाड़ी जैसा कि अधिनियम की धारा 2(14) में परिभाषित है।

9. हालाँकि, विद्वान न्यायाधीश ने इस न्यायालय के कई निर्णयों, विशेष रूप से यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम त्रिलोक चंद [(1996) 4 स्केल 22 = (1996) 4 एससीसी 362], साथ ही नए सहित विभिन्न अन्य निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इंडिया एश्योरेंस कंपनी बनाम कल्पना एवं अन्य। [(2007) 2 स्केल 227], राय है कि अपनाया जाने वाला उपयुक्त गुणक 10 था। उपरोक्त आधार पर निर्भरता का नुकसान 1,87,500/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने 2/3 को श्रम इनपुट के रूप में विभाजित किया, अर्थात, व्यवसाय में मृतक का व्यक्तिगत इनपुट और 1/3 को पूंजीगत संपत्ति से उपज के रूप में माना, मृतक की मृत्यु के कारण होने वाली हानि को 12,50,000 रुपये माना गया। बताते हुए:

> "6,25,000/- रुपये के शेष नुकसान की भरपाई परिवार द्वारा कारखाने को किराए पर देकर या पूंजीगत संपत्ति को समाप्त करने के बाद ब्याज के माध्यम से वार्षिक आय प्राप्त करने वाली वार्षिकी में निवेश करके की जा सकती है।"

10. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अशोक के. महाजन ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने केवल 10 के गुणक को लागू

करने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि अधिनियम से जुड़ी दूसरी अनुसूची के संदर्भ में, उपयुक्त गुणक जिसे लागू किया जाना चाहिए था वह 13 है। यह आग्रह किया गया था कि वार्षिक निर्भरता की गणना के प्रयोजन के लिए, इस प्रकृति के मामले में, उच्च न्यायालय को घटनाओं की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए था, अर्थात् मृतक जिसने ऋण लिया था 1985 में नोएडा में एक औद्योगिक भूखंड खरीदने के उद्देश्य से बैंक से 14,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया था।

11. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री एके डे ने तर्क दिया कि मृतक की आय का आकलन केवल शुद्ध कमाई पर किया जा सकता है और जो वास्तव में खो गया था वह उसका श्रम और उसके व्यवसाय को चलाने के लिए दूसरों का योगदान था और इस प्रकार, निर्भरता की हानि ऐसी सेवाओं के मूल्य या कौशल और ज्ञान की प्रकृति में श्रम के योगदान पर निर्धारित की जानी चाहिए जिसमें वह योगदान दे रहा था। यह आग्रह किया गया कि उनकी सेवाओं के मूल्य का संकेतक केवल व्यवसाय की लाभप्रदता हो सकता है जिसे रिकॉर्ड पर उचित सामग्री लाने पर दिखाया और स्थापित किया जाना चाहिए।

12. किसी व्यक्ति, जो परिवार का कमाऊ सदस्य था, की मृत्यु से उत्पन्न मुआवजे की राशि का निर्धारण बड़ी संख्या में कारकों पर निर्भर करेगा; उनमें से एक उसकी नौकरी या व्यवसाय की प्रकृति थी जो वह कर

रहा था। उक्त उद्देश्य के लिए, उसकी मृत्यु के समय की वास्तविक सकल आय को उस अधिकतम राशि में जोड़कर एक औसत सकल भविष्य की मासिक आय निकाली जानी चाहिए, जो उसे मिल सकती थी, यदि उसकी समय से पहले मृत्यु नहीं हुई होती।

विद्वान न्यायाधिकरण ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि थोड़े ही समय में, अपीलकर्ता बैंक से लिया गया पूरा ऋण चुकाने में सक्षम हो गया और इस प्रकार, एक औद्योगिक भूखंड का मालिक बन गया और इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रासंगिक समय पर उनकी आयु केवल 46 वर्ष थी, उन्होंने सोचा कि उनकी मृत्यु के समय उनकी आय दोगुनी हो गई होगी। हमारा मानना है कि विद्वान न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण सही था।

13. सरला दिक्षित बनाम बलवंत यादव [(1996) 3 एससीसी 179] में इस न्यायालय ने मृतक की भविष्य की संभावनाओं पर बहुत विस्तार से विचार किया। यह माना गया कि निर्भरता के नुकसान का पता लगाने वाली गुणक विधि को उचित मामले में लागू किया जाना चाहिए। इसमें अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णय पर विचार किया गया कि उक्त पद्धति उपयुक्त है। यह राय दी गई कि केवल गंभीर मामलों में ही उक्त पद्धति को छोड़ देना चाहिए। उचित गुणक को अपनाने के संबंध में, यह माना गया कि:

"7. जहां तकउचित गुणक को अपनाने का सवाल है, यह देखा गया कि जीवन और करियर में उन्नति की भविष्य की संभावनाओं को भी गुणक को बढ़ाने के लिए धन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जबकि गुणक दो कारकों पर निर्धारित होता है, अर्थात्, एक स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त ब्याज दर और मृतक या दावेदार की आयु, जो भी अधिक हो, गुणक का पता लगाना अधिक कठिन कार्य है। वास्तव में, कई कारकों को तराजू में रखना पड़ता है भविष्य की आकस्मिकताओं का मूल्यांकन करने के लिए। जरूरी नहीं कि भविष्य की सभी आकस्मिकताएँ हानिकारक हों।"

14. भारत में औसत जीवन प्रत्याशा भी उन कारकों में से एक है जिसे औसत सकल भविष्य की मासिक आय की गणना के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत में औसत जीवन प्रत्याशा अब 60-61 वर्ष है। व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों और आयकर के भुगतान आदि जैसी अन्य वैधानिक देनदारियों को घटाना आवश्यक है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव [(2008) 2 एससीसी 763] में इस न्यायालय ने कहा:

"17. इस न्यायालय ने आशा के हमारे समक्ष उठाए गए प्रश्नों का स्वयं समाधान नहीं किया। ऐसा प्रतीत नहीं होता

है कि किसी भी मिसाल पर ध्यान दिया गया था और न ही बदलती सामाजिक स्थिति और भुगतान किए जाने वाले भत्तों के आलोक में "उचित मुआवजे" शब्द पर विचार किया गया था। कर्मचारी पर आयकर या कोई अन्य कर लग भी सकता है और नहीं भी। "उचित मुआवजा" क्या होगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। संपूर्ण वेतन-पैकेट पर विचार करने का आधार वह है जो आश्रितों पर है मृतक की मृत्यु के कारण नुकसान हुआ है। यह पारिवारिक आय के लिए भविष्य में होने वाले नुकसान के मुआवजे की प्रकृति में है।

19. इसलिए, वह राशि, जो मृतक को उसके नियोक्ता द्वारा भत्तों के रूप में भुगतान की जानी थी, उसकी मासिक आय की गणना के लिए शामिल की जानी चाहिए क्योंकि वह परिवार में योगदान के माध्यम से उसकी मासिक आय में जोड़ दी गई होगी। उन लोगों के विपरीत जो उसके लाभ के लिए थे। हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि आय की उक्त राशि से, उसके बाद देय कर की वैधानिक राशि में कटौती की जानी चाहिए।

21. यदि शब्द "आय" के शब्दकोषीय अर्थ को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए, तो इसमें वे लाभ शामिल होने चाहिए, या तो धन के संदर्भ में या अन्यथा, जिन्हें आयकर या पेशेवर कर के भुगतान के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाता है। इसके कुछ तत्व करयोग्य हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं या कानून के तहत दी गई छूट के बिना अन्यथा करयोग्य होते।

25. "न्यायसंगत" अभिव्यक्ति को उसका तार्किक अर्थ भी दिया जाना चाहिए। हालाँकि यह कोई बोनस या लाभ का स्रोत नहीं हो सकता है, लेकिन क्या उचित और न्यायसंगत होगा, इस पर विचार करते समय सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

15. आमतौर पर और अपवादों के अधीन, मृतक की आय के 1/3 के बराबर एकमुश्त राशि, यानी, आय से रहने और विविध खर्चों की कटौती की जानी चाहिए। [सुनील कुमार बनाम राम सिंह गौड़ एवं अन्य देखें। [(2007) 12 स्केल 792]।

16. हालाँकि, हम ध्यान दे सकते हैं कि स्थायी विकलांगता के मामले में, जहाँ घायल को बहुत छोटी चीज़ के लिए भी दूसरे की सेवाओं पर

निर्भर रहना पड़ता है, उक्त राशि में कटौती करने के निर्देश पर जोर नहीं दिया जा सकता है।

17. इस प्रकार, 1/3 की कटौती सामान्य नियम है।

उपर्युक्त सिद्धांत को लागू करने पर, गुणक वार्षिक निर्भरता को जीवन प्रत्याशा से गुणा करके मृतक की आयु को घटाकर प्राप्त करेगा। उपर्युक्त आधार पर, हम मुआवजे की राशि की गणना के उद्देश्य से गुणक विधि की प्रयोज्यता पर विचार कर सकते हैं। उक्त विधि डेविस बनाम पॉवेल डफ़्रिन एसोसिएटेड कोलियरीज लिमिटेड [1942 (1) ऑल ईएलआर 657] में लागू की गई थी, जिसमें यह कहा गया था:

> "प्रारंभिक बिंदु मजदूरी की वह राशि है जो मृतक कमा रहा था, जिसका पता लगाना कुछ हद तक उसके रोजगार की नियमितता पर निर्भर हो सकता है। फिर यह अनुमान लगाया जाता है कि उसके अपने निजी और जीवन-यापन के खर्चों के लिए कितनी राशि की आवश्यकता थी या कितना खर्च किया गया था शेष राशि एक डेटाम या मूल आंकड़ा देगी जिसे आम तौर पर एक निश्चित संख्या में वर्षों की खरीद के बाद एकमुश्त राशि में बदल दिया जाएगा। हालांकि, उस राशि पर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए कर लगाया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, हो सकता

है कि विधवा ने फिर से शादी कर ली हो और इस तरह उस पर निर्भर रहना बंद कर दिया हो, और अटकलों और संदेह के अन्य मामले भी।"

त्रिलोक चंद (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा:

"7. इसी सिद्धांत को इस न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम बनाम सुभगवंती के मामले में याद किया था। इस मामले में मुआवजे का दावा एक राजमार्ग से सटे क्लॉक टॉवर के ढहने से हुई जान की हानि के कारण हुआ था। न्यायालय ने उपरोक्त दोनों निर्णयों का उल्लेख किया, और डेविस के मामले में निर्णय से निम्नलिखित अंश निकाला:

"प्रारंभिक बिंदु मजदूरी की वह राशि है जो मृतक कमा रहा था, जिसका पता लगाना कुछ हद तक उसके रोजगार की नियमितता पर निर्भर हो सकता है। फिर यह अनुमान लगाया जाता है कि उसके अपने व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों के लिए कितनी राशि की आवश्यकता थी या कितना खर्च किया गया था। शेष राशि एक डेटाम या मूल आंकड़ा देगी जिसे आम तौर पर एक निश्चित संख्या में वर्षों की खरीद के बाद एकमुश्त राशि में बदल दिया जाएगा। हालांकि, उस राशि पर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते

हुए कर लगाया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, हो सकता है कि विधवा ने फिर से शादी कर ली हो और इस तरह उस पर निर्भर रहना बंद कर दिया हो, और अटकलों और संदेह के अन्य मामले भी।"

हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र एसआरटीसी में। [(1999) 1 एससीसी 90], इस न्यायालय ने कानून को इस प्रकार बताया:

"32. जहां तकआम कानून के तहत नुकसान के आकलन के सामान्य सिद्धांत का सवाल है, यह तय है कि आर्थिक नुकसान का आकलन केवल एक तरफ से दावेदार को होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ के नुकसान को संतुलित करके किया जा सकता है। उसे लेकिन मृत्यु के लिए "आर्थिक लाभ" के साथ, जो किसी भी स्रोत से मृत्यु के कारण उसे मिलता है। दूसरे शब्दों में, यह दावेदार की मृत्यु के कारण हुए नुकसान और लाभ का संतुलन है। लेकिन इसे उस हद तक अपना रंग बदलना होगा जिस हद तक क़ानून ऐसा करना चाहता है।"

गुणक की पसंद के संबंध में, वॉल्यूम में इंग्लैंड के हैल्सबरी के नियम। 34, इस प्रकार कहता है:

"हालांकि, गुणक प्रत्याशा की अवधि के रूप में लिए गए वर्षों की संख्या से काफी कम है। चूंकि आश्रित अपने नुकसान का निवेश कर सकते हैं, भविष्य के नुकसान के संबंध में एकमुश्त पुरस्कार को ब्याज की प्राप्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए छूट दी जानी चाहिए निवेशित निधि, इरादा यह है कि आश्रित प्रत्येक वर्ष ब्याज और कुछ पूंजी आकर्षित करेंगे (ब्याज तत्व घट रहा है और पूंजी निकासी वर्षों के साथ बढ़ रही है), ताकि उन्हें हर साल उनके वार्षिक नुकसान के लिए मुआवजा दिया जा सके, और फंड होगा सभी आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए, उस उम्र में समाप्त हो जाएं जिसे अदालत सही उम्र मानती है। बीमारी, विकलांगता और बेरोजगारी जैसी जीवन की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखना होगा। बीमांकिक साक्ष्य स्वीकार्य है, लेकिन अदालतें प्रोत्साहित नहीं करती हैं ऐसे साक्ष्य। गणना अनुमानित ब्याज दर के चयन पर निर्भर करती है। व्यवहार में लगभग 4 या 5 प्रतिशत का चयन किया जाता है, और मुद्रास्फीति की उपेक्षा की जाती है। यह माना जाता है कि निश्चित ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर रिटर्न 4 से 5 प्रतिशत से बहुत अधिक है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के लिए मोटा और तैयार भत्ता बनाया जाता है। जहां वादी

उच्च करदाता है वहां गुणक बढ़ाया जा सकता है। गुणक परीक्षण की तिथि पर मजदूरी की दर पर आधारित है। कुल आंकड़े पर कोई ब्याज की अनुमति नहीं है।"

यह कानून लाभकारी है, इसलिए इसके प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए, लेकिन यह भी अच्छी तरह से तय है कि यह अन्यायपूर्ण संवर्धन पर विचार नहीं करता है। हालाँकि, हम देख सकते हैं कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चार्ली[(2005) 10 एससीसी 720] में, इस न्यायालय ने कहा था:

"14. गुणक विधि में मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्भरता या गुणक के नुकसान का पता लगाना और एक उपयुक्त गुणक द्वारा गुणक को पूंजीकृत करना शामिल है। गुणक की पसंद मृतक की उम्र (या वह) के आधार पर निर्धारित की जाती है दावेदारों की, जो भी अधिक हो) और यह गणना करके कि स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए उचित ब्याज दर पर निवेश किए जाने पर कौन सी पूंजी राशि, वार्षिक ब्याज के माध्यम से गुणक प्राप्त करेगी। यह सुनिश्चित करने में, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए इस तथ्य से कि अंततः पूंजीगत राशि का उपभोग

भी उसी अवधि में किया जाना चाहिए जिसके लिए निर्भरता बनी रहने की उम्मीद है।"

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पेट्रीसिया जीन महजन [(2002) 6 एससीसी 281] में, हालांकि, यह न्यायालय महाप्रबंधक, केरल एसआरटीसी बनाम सुसम्मा थॉमस[(1994) 2 एससीसी 176] में पहले के निर्णयों का भी पालन कर रहा है। त्रिलोक चंद (सुप्रा), अभिनिर्धारित:

"16 इस प्रकार उपरोक्त निर्णयों से जो उभरता है वह यह है कि अदालत को मुआवजे की उचित राशि पर पहुंचने के लिए गुणक प्रणाली का पालन करना चाहिए, और एकरूपता और निश्चितता बनाए रखने की दृष्टि से भी। उच्च गुणक के उपयोग को अस्वीकृत कर दिया गया है और इसे इस बात पर जोर दिया जाता है कि यह 18 से अधिक गुणक नहीं हो सकता। जैसा कि पहले उद्धृत टिप्पणियों से स्पष्ट होगा, उद्धृत उदाहरण के अनुसार, किसी विशेष मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में भिन्न हो सकता है, जहां एक कुंवारे व्यक्ति की 45 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। उचित गुणक का चयन करने के लिए उसके आश्रित माता-पिता की आयु प्रासंगिक हो सकती है। इसका मतलब यह है

कि अनुसूची में दिए गए गुणक से कम गुणक को किसी मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। बाद के मामलों में भी इस न्यायालय ने लिया है वही विचार है कि मुआवजे की राशि की गणना के लिए गुणक प्रणाली एक अधिक उपयुक्त और उचित तरीका है। लता वाधवा बनाम बिहार राज्य का संदर्भ लिया जा सकता है। सुसम्मा थॉमस और अन्य अंग्रेजी निर्णयों के मामले में निर्णय पहले संदर्भित निर्णयों में माना गया है। अर्थात्, डेविस बनाम टेलर, डेविस बनाम पॉवेल डफ़्रिन एसोसिएटेड कोलियरीज लिमिटेड और मैलेट बनाम मैकमोनागल का उल्लेख किया गया है।"

18. इसलिए, कुल मिलाकर, न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा था कि दूसरी अनुसूची में उल्लिखित गुणक को मार्गदर्शक माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है।

19. दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट गुणक मृत्यु के मामलों में मुआवजे की गणना के लिए निर्णायक नहीं हो सकता है। वास्तव में, गुणक शब्द का उपयोग केवल स्थायी विकलांगता के मामले में क्षति की गणना के उद्देश्य से किया गया है, न कि मृत्यु के मामले में, जैसा कि इसमें संलग्न नोट 5 और 6 से पता चलता है।

20. दूसरी अनुसूची उन व्यक्तियों को मुआवजे की राशि के भुगतान का प्रावधान करती है जिनकी आय मृतक की उम्र के आधार पर प्रति वर्ष 3,000/- रुपये से 40,000/- रुपये तक है; उदाहरण के लिए, यदि मृतक की आयु 15 वर्ष है, तो देय मुआवजे की राशि 60,000/- होगी, लेकिन जहां वार्षिक आय 3,000/- रुपये है, वहां 50,000/- रुपये की राशि निर्दिष्ट की गई है, भले ही मृतकों की उम्र 35 से 65 साल के बीच है।

21. इसलिए, संसद ने सोचा था कि 50,000/- रुपये उन व्यक्तियों के कानूनी प्रतिनिधियों को देय मुआवजे की न्यूनतम राशि होनी चाहिए जिनकी वार्षिक आय 3,000/- रुपये प्रति माह है। उक्त उद्देश्य के लिए, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट गुणक की कोई भूमिका नहीं है। दूसरी अनुसूची में गुणक के अभाव में भी, देय मुआवजे की राशि उसमें निर्दिष्ट गुणक के बावजूद समान होगी।

22. हालाँकि, हम देख सकते हैं कि किसी दिए गए मामले में, यहां तक कि दूसरी अनुसूची के संदर्भ में भी, जहां मुआवजा बिना किसी गलती के दायित्व के आधार पर देय है, मुआवजे की राशि गलती दायित्व के मामले में दूसरी अनुसूची उस राशि से अधिक हो सकती है जो इसमें निर्दिष्ट की गई है।

23. उचित मामले में, प्रश्न पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

24. हालाँकि, इस मामले में, मृतक एक व्यापारी था। परिवार की निर्भरता का वास्तविक नुकसान व्यवसाय चलाने में उनके योगदान से हुआ। व्यवसाय की संपत्तियाँ बनी रहीं। इसलिए, उस कारक को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि निर्धारित की जानी आवश्यक थी।

25. अतः 10 के गुणक का प्रयोग कानून की दृष्टि से बुरा नहीं कहा जा सकता। इस हिसाब से मुआवज़े की राशि 12,50,000/- रुपये होगी, हालाँकि, हमारी राय में, उच्च न्यायालय की यह राय पूरी तरह से सही नहीं हो सकती है कि शेष नुकसान की भरपाई की जा सकती है। हालाँकि, हमें उक्त प्रश्न पर और अधिक गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी राय है कि उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय सही है।

26. इसलिए, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया गया है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निधि शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।